

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - विस्वा

तहसील - बडकोट, जिला - उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 3.11.62 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट (उत्तरकाशी) के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत विस्वा द्वारा दिनांक 02/02/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विस्वा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /-

ग्राम सचिव

प्रधान [Signature]
ग्राम पंचायत मजिथाली
वि०स०-बौगांव (उत्तरकाशी)
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र - 23.1

दिनांक 02/02/2024 के ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - बिल्वा

तहसील - बडकोट, जिला - उत्तरकाशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिवान सिंह S/o जुद्धवीर सिंह	दिवान सिंह
2	सुजान सिंह S/o साब सिंह	सुजान सिंह
3	देवीन लाल S/o लक्ष्मी देवी	देवीन लाल
4	बैम सिंह S/o पुरत सिंह	बैम सिंह
5	रवजान सिंह S/o लाल सिंह	रवजान सिंह
6	चैतन्य S/o बुला राम	चैतन्य
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

प्रधान बिल्वा
ग्राम पंचायत मजियाली
वि०स० नौगाव (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बडौगी

तहसील - बडकोट, जिला - उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 7.563 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट (उत्तरकाशी) के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

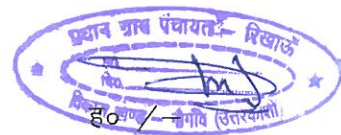
उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत बडौगी द्वारा दिनांक 20.11.2022 को सम्मपन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बडौगी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / -

ग्राम सचिव



ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

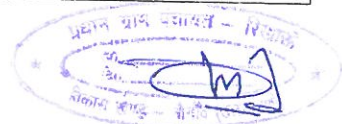
प्रपत्र - 23.1

दिनांक 20/12/2023 के ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कड़ीगी

तहसील - बडकोट, जिला - उत्तरकाशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रुक्मेश सिंह S/O जय-राम सिंह	रुक्मेश सिंह
2	किशन सिंह S/O शंकर सिंह	किशन सिंह
3	शुजील सिंह S/O केशव सिंह	शुजील सिंह
4	राजेश सिंह S/O जयलाल सिंह	राजेश सिंह
5	गुग्गुमाह सिंह S/O अमर सिंह	गुग्गुमाह सिंह
6	राजेश सिंह S/O वचन लाल	राजेश सिंह
7	मिजान सिंह S/O बरधन सिंह	मिजान सिंह
8	सुखनारायण सिंह S/O नारायण सिंह	सुखनारायण सिंह
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		



ह०/- ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के सिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सौली

तहसील - बडकोट, जिला - उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के सिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 0.597 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट (उत्तरकाशी) के पक्ष में भरत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत सौली द्वारा दिनांक 18-12-2023 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के सिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

श्याम लाल
सभासद वार्ड न०-7 मुलाणा
नगर पंचायत नौगाँव (उत्तरकाशी)

ह० /-

ग्राम सचिव

ह० /-

ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

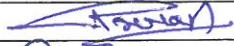




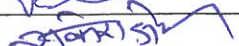
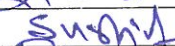

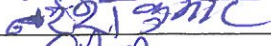

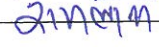
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र - 23.1

दिनांक 18/12/2023 के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - सौली

तहसील - बडकोट, जिला - उत्तरकाशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुल्लाल	
2	दीपक शर्मा	
3	बेनी लाल	
4	कुसदीप	
5	पसेश	
6	शंकराचर	
7	पुशील रंगा विद्यालाल	
8	विद्यालाल	
9	गरेश कुमार	
10	मीनचम	
11	शंभुलाल	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ह०/- ग्राम प्रधान

शंभुलाल

समाप्त बोर्ड नं-7 मुलीगा
ग्राम पंचायत नौगाँव उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) का तरी खुद से सुराडीगाव कि.मी. 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 26.00 कि.मी.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

* उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत 210 डी.टी. राजमार्ग (123) 507 कि.मी. 75-101 (आरक्षित वन भूमि 0.900 हे० रेंज सुराडीगाव, सिविल एवं सोयम वन भूमि 30.960 हे०, वन पंचायत भूमि हे०), अर्थात् कुल 31.860 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1- | श्री उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- | श्री बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि 210 डी.टी. राजमार्ग (123) 507 कि.मी. 75-101 परियोजना हेतु 31.860 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत
 परियोजना के निर्माण हेतु 31.860 हे० वन भूमि का इस्ताना
 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
 व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील बड़कोट
 जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील बड़कोट
 जनपद उत्तरकाशी

120

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

Name of Project- NH N. 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Motor Road.

No. 37.....

Dated 27-12-14


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 31.860 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NH Barkot for Construction of NH N. 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Km. 75.00 to 101 (Thatri Khad to Naugaon) in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Naugaon village in Barkot tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 31.860 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above


(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.

ANNEXURE**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 31.860 hect for the construction of NH 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Km 75.00 to 101 (Thatri Khad to Naugaon) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi

Dated: 27.12.14


(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय मार्ग - 123 (507) वाली बड़ोई
मुराही गांव जिमी 75.00 हे। 101.00 के क्षेत्र में (लम्बाई 26-00 बरफी)
हस्तांतरण प्रमाण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रिसाऊ
तहसील बड़ोई जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के लैन चौकीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि Nil हे। रेंज 142 सिविल सोयम भूमि 11.127 हे। वन पंचायत भूमि 11.127 हे। अर्थात् कुल 11.127 हे। वन भूमि का 2006/2007 12.2 उत्तरकाशी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिसाऊ द्वारा दिनांक 11.12.2007 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिसाऊ बड़ोई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2006/2007 12.2 उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर अनापत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिकाम पंचायत रिसाऊ
बेबलस खण्ड नौगाँव (30का0)



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 11/10/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दिलवाड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①-	अमर सिंह पंवार 5/0 स्व. की गुलाब सिंह	अमर सिंह
②-	राजेश्वर सिंह पंवार 5/0 श्री मैथर सिंह	राजेश्वर सिंह
③-	अमर सिंह पंवार 5/0 श्री लखवी राम	अमर सिंह
④-	सुरेश सिंह पंवार 5/0 श्री कमल सिंह	सुरेश सिंह
⑤-	अमर सिंह 5/0 श्री अमर सिंह	अमर सिंह
⑥-	वचन सिंह पंवार 5/0 स्व. + सिया सिंह	वचन सिंह
⑦-	विजय सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री राम राम	विजय सिंह
⑧-	सुरेश सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
⑨-	गुलाब सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री लखी राम	गुलाब सिंह
⑩-	महावीर सिंह 5/0 स्व. श्री सुरेश सिंह	महावीर सिंह
⑪-	अमर सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री गुलाब सिंह	अमर सिंह
⑫-	अमर सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री धरम सिंह	अमर सिंह
⑬-	चमन सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री धरम सिंह	चमन सिंह
⑭-	शैलेश पंवार 5/0 स्व. श्री वचन सिंह पंवार	शैलेश पंवार
⑮-	अरुण पंवार 5/0 स्व. श्री शैलेश सिंह पंवार	अरुण पंवार
⑯-	सुरेश पंवार 5/0 स्व. श्री वचन सिंह पंवार	सुरेश पंवार
⑰-	तेतर सिंह पंवार 5/0 स्व. श्री सीताराम	तेतर सिंह
⑱-	प्रतिभा देवी 5/0 स्व. श्री प्रेम सिंह	प्रतिभा देवी
⑲-	जयवीर सिंह 5/0 स्व. श्री किकर सिंह	जयवीर सिंह
⑳-	कमल सिंह 5/0 स्व. श्री कैशिया सिंह	कमल सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में वाणीय राजमार्ग 123 (2003) अन्तर्गत वन भूमी
 गांव जि. की. 75-00 के 111 के के दो लेन - पौड़ीवरण हेतु वन भूमि
 हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वाणीय
 तहसील वाणीय, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वाणीय परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि Nil हे० रेंज वाणीय सिविल सोयम भूमि 1.199 हे०, वन पंचायत भूमि Nil हे०) अर्थात् कुल 1.199 हे० वन भूमि का वाणीय के आदिवासी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत वाणीय द्वारा दिनांक 10/07/2007 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वाणीय के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि वाणीय के आदिवासी/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर वाणीय
 80/4 पंचायत वाणीय
 ग्राम सचिव वाणीय



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 11/11/2014 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कठारी

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शुरेश जी 5/1 तुलाराम जी 5/1 कठारी	
2	श्री सुभारी जी 5/1 श्री चंद जी 10/1 कठारी	
3	श्री सुरेश दत्त जी 5/1 श्री विजयराज कठारी	
4	श्री लाल गाल जी 5/1 श्री सिमराज	
5	श्री बचनदास 5/1 श्री सन्ता दाल	
6	ममलाल जी	
7	राम प्रसाद	राम प्रसाद
8	श्री गोविंद	
9	लालराम	लालराम
10	राधवल्लभ	
11	हरना लाल	
12	शक्ति	शक्ति
13	काला	दिवानदास
14	दिवानदास	दिवानदास
15	शुभदास	शुभदास
16	लालराम	लालराम



परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) धातरी खंड से
मुराडी गांव कि.मी. 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 26.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खुमोली
तहसील बड़मोह, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमे NIL हे0 रेंज सिविल सोयम भूमि 0.821 हे0, वन पंचायत भूमि NIL हे0) अर्थात् कुल 0.821 हे0 वन भूमि का उत्तरकाशी जिला वन विभाग/तहसील के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खुमोली द्वारा दिनांक 30-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खुमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तरकाशी जिला वन विभाग/तहसील प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

खुमोली मन्त्री
ग्राम पंचायत

80/-
ग्राम प्रधान

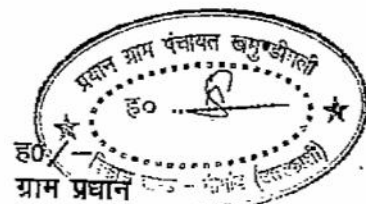
नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 30-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खुम्डी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रमेश प्रसाद नौटियाल खोसकीभवा	<i>[Signature]</i>
(2)	बुद्धाराम नौटियाल	<i>[Signature]</i>
(3)	विनय नौटियाल	<i>[Signature]</i>
(4)	प्रदीप नौटियाल	<i>[Signature]</i>
(5)	सुरेंद्र चौधरी	<i>[Signature]</i>
(6)	राजेश मेहता	<i>[Signature]</i>
7-	सुरेंद्र राणा	<i>[Signature]</i>
8-	लक्ष्म नौटियाल	<i>[Signature]</i>
9	सुरेंद्र सिंह राणा	<i>[Signature]</i>
10	प्रदीप नौटियाल (बन सरपंच) व स.	<i>[Signature]</i>
11-	गजेन्द्र लाल नौटियाल	<i>[Signature]</i>
12-	जैरा शाह	<i>[Signature]</i>
13		
14		
15		
16		



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) बावली (ग्रैंड से मुखाई) गांव जि० भी 75.00 से 101.00 तक के क्षेत्र में (ग्रामीण) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
लम्बई 26.07.2014

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बावली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) जि० भी 75.00-101.00
(आरक्षित वन भूमि Nil हे० रेंज , सिविल एवं सोयम वन भूमि 13.147 हे०,
वन पंचायत भूमि Nil हे०), अर्थात् कुल 13.147 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील बावली) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| 1- | श्री <u>अशोक कुमार झा</u> | उपजिलाधिकारी | <u>बावली</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>जी.पी. शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>बावली</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>रमेश चन्द्र झा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>बावली</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्रीमती <u>राजेश्वरी झा</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>बावली</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) जि० भी 75.00 से 101.00 परियोजना हेतु हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड वर्मा परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (802)
परियोजना के निर्माण हेतु 13.147 हे० वन भूमि का हस्तांतरण
प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय अधिकार समिति
तहसील- वर्मा
जनपद- उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय अधिकार समिति
तहसील- वर्मा
जनपद- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) आगरी ब्रिज के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव।
गोबिन्द जी 75-00 है। 101 लड़के ~~असह्य~~ के लेन-चौड़ीकरण हेतु वन-भूमि (लगभग 6.313 हे. 26-10 प्रो.मी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिथुली
तहसील बड़ोली जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के लेन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन नूनि Mill हे० रेंज सिविल सोयन भूमि 6.313 हे० वन पंचायत नूनि Mill हे०) अर्थात् कुल 6.313 हे० वन भूमि का 26-10 मार्च 2010 दिनांक/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिथुली द्वारा दिनांक 12-11-2011 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन नूनि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन नूनि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिथुली के ग्रामवासियों को उक्त वन नूनि 26-10 मार्च 2010 दिनांक/संस्था के पक्ष में अनापत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सभा/पंचायत
ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत सिथुली
ह०/रजनीश
ग्राम प्रभारी
निवासी खण्ड अधिकारी (उत्तरकाशी)

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी नूनि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 12/11/2011 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिंगुणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
	अजय सिंह	अजय सिंह
	मनम सिंह	मनम सिंह
	बीरम सिंह	बीरम सिंह
	पतव सिंह	पतव सिंह
	अमर सिंह	अमर सिंह
	बिरफा सिंह	बिरफा सिंह
	परम सिंह	परम सिंह
	चतर सिंह	चतर सिंह
	हुक्म सिंह	हुक्म सिंह
	उदीप सिंह	उदीप सिंह
	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
	मल्लवार सिंह	मल्लवार सिंह
	दिवान	दिवान
	चन्दू सिंह	चन्दू सिंह
	सुशत सिंह	सुशत सिंह
	सुनील सिंह	सुनील सिंह
	चन्द्रमोहन सिंह	चन्द्रमोहन सिंह

लारखीराम सिंह
प्रेम सिंह

मारी राम
प्रेम सिंह
गुप्ता

ह0/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (503) वाली बड़ोई
बुड़ी गांव की 75.00 से 101.00 के क्षेत्र में जंगल वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 26.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पिपिआरा

तहसील बडोई जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बडोई परियोजना
के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे0 रेंज सिविल सोयम
भूमि 1.848 हे0 वन पंचायत भूमि NILL हे0) अर्थात् कुल 1.848 हे0 वन भूमि का
राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (503) वाली बड़ोई विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पिपिआरा द्वारा दिनांक.....को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,
2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त
वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा
है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया
गया कि ग्राम पिपिआरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (503) वाली बड़ोई
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम पंचायत पिपिआरा अधिकारी

ग्राम पंचायत

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि इन्वाइट हो रही है, तो तदनुसार
उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को
उपलब्ध कराया जायेगा।



दिनांक 5-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~नौ~~ पिप्राधार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरत सिंह रावत	सुरत सिंह
2	राम सिंह रावत	राम सिंह रावत
3	जयवीर सिंह रावत	जयवीर सिंह
4	कृपाल सिंह रावत	कृपाल
5	भरत सिंह रावत	B.S. सिंह
6	दिवेन्द्र सिंह रावत	दिवेन्द्र सिंह
7	राम मारा	राम मारा
8	राजेन्द्र सिंह रावत	राजेन्द्र सिंह
9	महेश्वर सिंह रावत	महेश्वर
10	बचन सिंह रावत	बचन सिंह
11	चैत सिंह रावत	चैत सिंह
12	नाराम सिंह रावत	नाराम सिंह
13	सरदार सिंह रावत	सरदार सिंह
14	भूरधाम	भूरधाम
15	जगदीश रावत	जगदीश
16	रविंद्र रावत	रविंद्र
17	दिवकर रावत	दिवकर
18	बहादुर रावत	बहादुर



ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जलपट्टा उत्तरकाशी में राबर्ट्स राजमार्ग 123 (503) आन्वेषण से
 कुम्भी गांव वि.सं. 75-00 से 101-00 के लिए नई वन अधिकार हस्तांतरण
 प्रस्ताव।
 (कार्यांक 26.00 वि.सं.)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत राबर्ट्स राजमार्ग 123 (503) वि.सं. 75-00 से 101-00 तक
 (आरक्षित वन भूमि 111/1 हे० रेंज 111/1 , सिविल एवं सोयम वन भूमि 8/16/1 हे०,
 वन पंचायत भूमि 111/1 हे०), अर्थात् कुल 811/1 हे० वन भूमि का हस्तांतरण
 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
 परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
 (तहसील बड़कोट) की दिनांक 26/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
 बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| 1- | श्री <u>देव प्रताप मादव</u> | उपजिलाधिकारी | <u>बड़कोट</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>श्री श्री सिंह</u> | उप प्रमाणीय वनाधिकारी | <u>बड़कोट</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>अनापति अधिकारी</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>पंचायत</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>अनापति</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>पंचायत</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी ने
 अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
 कि राबर्ट्स राजमार्ग 123 (503) वि.सं. 75-00 से 101-00 तक परियोजना
 हेतु हस्तांतरण हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष
 में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत
 वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से
 पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति
 एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008
 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,
 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में
 ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
 समिति द्वारा अनापति जारी की जा सकती है।

(५३)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कड़वा परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(823)
परियोजना के निर्माण हेतु 8.161 हे० वन भूमि का हस्तांतरण
प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कड़वा
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कड़वा
जनपद उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) चाररी बड़ से बुराई गांव कि० नं० 75.00 से 101.00 तक के लेन में चाररी बड़ वन में वृक्ष हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लान्सार्ड-26.08.2007)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुवा

तहसील कुवा, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत चौ लेन - चाररी बड़ परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि है 0 रेंज है सिविल सोयम भूमि 0.8000 हे० वन पंचायत भूमि है 0) अर्थात् कुल 0.8000 हे० वन भूमि का उत्तरकाशी जिला वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुवा द्वारा दिनांक 26/08/07 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तरकाशी जिला वन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम वि० अधिकारी
ग्राम पंचायत कुवा
दि० 26/08/07 नौगाँव (उ०का०)
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 17/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुवा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	जमसिंह	
②	जगतदास	जगतदास
③	टिकराज	टिकराज
④	सुरपाल	सुरपाल
⑤	लालदास	लालदास
⑥	मंगलदास	मंगलदास
⑦	अनारसिंह	अनारसिंह
⑧	बनारसिंह	बनारसिंह
⑨	राजबंसिंह	राजबंसिंह
⑩	जीलसिंह	जीलसिंह
⑪	बुलसिंह	बुलसिंह
⑫	फूलक सिंह	फूलक सिंह
⑬	किसनसिंह	किसनसिंह
	अभिपाल	अभिपाल



परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में खेती राजमार्ग 123(502) मातृ लैंड से जुड़ी गांव छिन्नी 35.00 से 101 रु के क्षेत्र-चौडीकरण वन भूमि (लम्बाई 26.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जुडी

तहसील बुधोद जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत चौडीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 11.44 हे० रेंज सिविल सोयन भूमि 3.674 हे०, वन पंचायत भूमि 11.44 हे०) अर्थात् कुल 3.674 हे० वन भूमि का राजमार्ग 123(502) मातृ लैंड से जुड़ी क्षेत्र के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जुडी द्वारा दिनांक ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राजमार्ग 123(502) मातृ लैंड से जुड़ी क्षेत्र के पक्ष में प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/- ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव ...



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 16/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जरडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
2	शुश्रीक सिंह	शुश्रीक सिंह
3	सरदार सिंह	सरदार सिंह
4	मनमोहन सिंह	मनमोहन सिंह
5	दीपक सिंह	दीपक सिंह
6	मदन सिंह	मदन सिंह
7	पैना सिंह	पैना सिंह
8	जय सिंह	जय सिंह
9	रतन सिंह	रतन सिंह
10	धनवीर	धनवीर
10	जै-दर सिंह	जै-दर सिंह
12	रजनीश सिंह	रजनीश सिंह

ग्राम पंचायत जरडा
होम मिनि
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (502) बायीं लड़ से सुराड़ी, गांव नं० 75.00 से 10.00 तक के दो लैन चौड़ीकरण हेतु वन-कृषि हस्तासं (ला.नं० 26.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (502) 75.00 से 10.00 तक
(आरक्षित वन भूमि हे० रेंज , सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.424 हे०,
वन पंचायत भूमि हे०), अर्थात् कुल 4.424 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| 1- | श्री <u>देवमूर्ति मादव</u> | उपजिलाधिकारी | <u>बड़कोट</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>मि० पी० सिंह</u> | उप प्रमाणीय वनाधिकारी | <u>बड़कोट</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>माननीय मादव</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>बड़कोट</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>अमरिन्द्र</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत | <u>बड़कोट</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (502) बायीं लड़ से सुराड़ी परियोजना हेतु 4.424 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

103

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बम्बोले परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान राजमार्ग 123 (523) परियोजना के निर्माण हेतु 4.424 हे० वन भूमि का हस्तांतरण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सख्त प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बम्बोले
जनपद- उदयपुर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बम्बोले
जनपद- उदयपुर

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग-123(507) भारतीय नदी से मुन्गा गांव न
किमी 75.00 से 101.00 तक के दो लेन-कॉन्वेयरर हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
(लम्बाई 26.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारी मुन्गा

तहसील बिड़वाट जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दो लेन-कॉन्वेयरर परियोजना के निर्माण हेतु (आवश्यक वन भूमि 0.900 हे० रेंज भुगारमुन्गा सिविल सोयम भूमि 3.284 हे०, वन पंचायत भूमि 4.184 हे०) अर्थात् कुल 4.184 हे० वन भूमि का उत्तरकाशी जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारी मुन्गा द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारी मुन्गा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि मुन्गा गांव नदी से मुन्गा गांव तक प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत धारी मुन्गा
विकास अधिकारी (उ०का०)



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 26/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारीगुलावा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामलाल	रामलाल
2	मनोज	M. J.
3	वेणीलाल	वेणीलाल
4	रामेश जैन	रामेश जैन
5	दशरथलाल	दशरथ
6	विहालाल	विहालाल
7	श्रीमती विमला	सी. म. मा.
8	पताप	
9	मरेश	
10	सुनीलराजा	Sunil Raja
11	मोमू देवी	Mommu Devi
12	दिपकराजा	दीपकराजा
13	विरेंद्र प्रसाद चौहान	विरेंद्र प्रसाद चौहान
14	सुशीलराजा	सुशीलराजा
15	सुनील राव	सुनील राव
16	दीपक राव	दीपक राव
17	अरवि	अरवि
18	अश्विनी	अश्विनी

ह0/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) कागरी पथ से मुराडी गांव कि.मी. 75.00 से लव के के निम-मौड़ीवरा) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 26.00 कि.मी.)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) 75.00 से 101.00 नं०
(आरक्षित वन भूमि 5.400 हे० रेंज धूमसरी), सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.104 हे०,
वन पंचायत भूमि हे०), अर्थात् कुल 4.184 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण
..... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---------------|---------|
| 1- | श्री <u>देव प्रताप सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | <u>बड़कोट</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>जी.पी. सिंह</u> | उप प्रमाणीय वनाधिकारी | <u>बड़कोट</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>आर.पी. शर्मा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>नीगाव</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>क.पी. रीवा चन्द</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र <u>पंचायत किम्मी</u> | | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) 75.00 से 101.00 नं० परियोजना हेतु हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(104)

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बडकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123/503
परियोजना के निर्माण हेतु 4.184 हे० वन भूमि का हस्तांतरण
प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-बडकोट
जनपद-उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-बडकोट
जनपद-उत्तराखण्ड

108

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(502) का सी बर्ड से
मुराई गान किमी 75.00 से 101.00 तक के लेन चौड़ाई हेतु वन-भूमि
हस्तांतरण प्रमाण (लम्बाई 26.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जोगांव

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के लैन चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 2146 हे० रेंज M.P.L.C, सिविल सोयम भूमि 2376 हे०, वन पंचायत भूमि M.P.L.C हे०) अर्थात् कुल 2376 हे० वन भूमि का उत्तरकाशी जिला विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोगांव द्वारा दिनांक 20/11/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरोक्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तरकाशी जिला विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



हो / -
ग्राम प्रधान

जोगांव
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत जोगांव
 जिला विकास विभाग उत्तरकाशी

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की किसी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उचित विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाना।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 25/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नौगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बिजय रावत नौगांव	
2.	जगतार सिंह S/O जगतार सिंह	
3.	काशमीर सिंह S/O पमेली सिंह	
4.	गौरव S/O जगतार सिंह	
5.	रणवीर सिंह रावत S/O दलीप सिंह	
6.	जयपाल सिंह S/O बालक सिंह	
7.	जयदेव सिंह S/O लालचंद रावत	
8.	शमशेर सिंह रावत	
9.	लोकेश चन्द बजाज	
10.	का. वन्दनलाल	
11.	दीपक लाल	
12.	वन्दन सिंह	
13.	प्रभाकर सिंह	
14.	रविन्द्र सिंह	
15.	भोजन सिंह	
16.	प्रभाकर सिंह	
17.	सोहन रावत	
18.	वन्दन रावत	
19.	भुरगु सिंह	
20.	राजू लाल	
21.	आमर सिंह	

अश्वमेध चक्रवर्ती

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) भारतीय नदी से मुराही
गांव निजी 35.00 से 101.00 तक के क्षेत्र-विकास हेतु वन-भूमि हस्तान्तरण
(लम्बाई-26.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़गोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड बड़गोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) निजी 35.00 से 101.00 तक
(आरक्षित वन भूमि हे0 रेंज बड़गोला, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.376 हे0,
वन पंचायत भूमि हे0), अर्थात् कुल 0.376 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील बड़गोला) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|----------------------------|--|----------------|---------|
| 1- | श्री <u>देव शर्मा जादव</u> | उपजिलाधिकारी | <u>बड़गोला</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>जी. पी. 198</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>बड़गोला</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>मान. जादव</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>बड़गोला</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>सोहन रावत</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र <u>पंचायत नौगांव</u> | <u>बड़गोला</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) 35.00 से 101.00 परियोजना
हेतु हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष
में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत
वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से
पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़गोला द्वारा अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,
2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में
ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(11)

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कैलाश परिक्षेत्र के अन्तर्गत वा.प.न.स.स. 123 (502)
परियोजना के निर्माण हेतु 0.376 हे० वन भूमि का हस्तांतरण
प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप-जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कैलाश
जनपद उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कैलाश
जनपद उत्तराखण्ड

परियोजना का नाम :- सर्वोच्च न्यायालय जनपद उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507)
भारत सरकार से मुद्राई गांव कि० मी० 75.00 से 101.00 तक दे लेन-गोड़ीवरण
देव मन शक्ति हस्तान्तरण प्रमाण (लम्बाई 26.00 मि० मी०)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुंगर

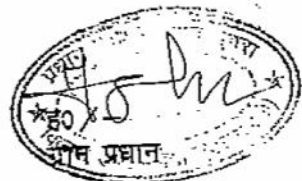
तहसील कडवा जिला उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दे लेन-गोड़ीवरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन नूनि NILL हे० रेंज सिविल सोयम भूमि 0.623 हे०, वन पंचायत नूनि NILL हे०) अर्थात् कुल 0.623 हे० वन भूमि का राष्ट्रिय राजमार्ग 123 (507) के निर्माण हेतु आदेशित/सत्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुंगर द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन नूनि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन नूनि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुंगर के ग्रामवासियों को उक्त वन नूनि राष्ट्रिय राजमार्ग 123 (507) के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह० 123
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत मुंगर
 नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी नूनि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 24/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मुंगरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	उपेन्द्र सिंह गभारी S/O बलबल सिंह	
2.	सुरेश परमा S/O जोगा सिंह	
3.	लक्ष्मण परमा S/O अश्वरूप सिंह	
4.	जयपू सिंह जयपाल सिंह	
5.	जयजोरा परमा	
6.	जोगानन्द	
7.	जगन्नाथ सिंह	
8.	जोगा सिंह	
9.	विक्रम सिंह	
10.	बलबल	
11.	काशीप्रसाद सिंह	
12.	विजय सिंह	
13.	जयपाल	
14.	अजयपाल	
15.	बलबल सिंह	
16.	कर्म सिंह	
17.	हरिप्रसाद सिंह	
18.	सुरेश सिंह	
19.	महेन्द्र सिंह	
20.	श्री अश्वरूप सिंह	

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- जनपद उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507) धारसी एंड से मुवाडी
गांव की सीमा 75.00 से 101.00 रु दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण
प्रस्ताव।
(नम्बर 26.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुवाडी

तहसील बड़कोट जिला उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत के लेन चौकी परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि NILL हे० रेंज सिविल सोयम भूमि १.८९५ हे०, वन पंचायत भूमि NILL हे०) अर्थात् कुल १.८९५ हे० वन भूमि का २६.०० मी० चौ० विस्तार/सत्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुवाडी द्वारा दिनांक २००८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुवाडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि २६.०० मी० चौ० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

ह०/-
ग्राम प्रधान



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 28/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मुन्नाड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पद्मनाभ/लाल	
2-	लालमोय लाल	
3-	चिरजी लाल	चिरजी लाल
4-	पूनीन चन्द	
5-	प्यार लाल	
6-	विजय	
7-	हनुमान मोहन चन्द (मोहन)	
8-	सोहन लाल	
9-	पेम लाल	
10-	सुशील रानी	
11-	रजेंद्र कुमार	
12-	विजय लाल	
13-	अम-चन्द	
14-	रज-चन्द	
15-	लाल-चन्द	
16-	विजय-लाल	
17-	अम-चन्द	
18-	पद्म लाल	
19-	रजेंद्र लाल	

ह0/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) के व्यापक लव्ड से मुराड़ी
ग्राम निजी 75.00 हे. 101.00 हे. के क्षेत्र में जमीन के हस्तान्तरण
प्रस्ताव
(तहसील 26.00 कि.मी.0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) निजी 75.00 हे. 101.00 हे.
(आरक्षित वन भूमि 80 रेंज, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.5.12 हे.0,
वन पंचायत भूमि 80), अर्थात् कुल 1.5.12 हे.0 वन भूमि का हस्तान्तरण
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील बड़कोट) की दिनांक 20/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 1- | श्री कि.मणि यादव | उपजिलाधिकारी | बड़कोट | अध्यक्ष |
| 2- | श्री श्री 0 पं. सिंह | उप प्रमाणीय वनाधिकारी | बड़कोट | सदस्य |
| 3- | श्री श्री 0 पं. श्री | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | नौगांव | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री श्री 0 पं. श्री | बी0डी0सी0 क्षेत्र | पंचायत मुराड़ी | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (507) निजी 75.00 हे. 101.00 हे. परियोजना
हेतु 80 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष
में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत
वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से
पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,
2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में
ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

112

वैतक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बनौर परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनार्ण 123/507)
परियोजना के निर्माण हेतु 1.5/7 हे० वन भूमि का हस्तांतरण
प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बनौर
जनपद उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बनौर
जनपद उत्तराखण्ड